

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 3538

मंगलवार, 17 दिसम्बर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

इन्वेस्ट इंडिया और एफडीआई

3538. श्री गोडम नागेश:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में प्राप्त कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को सुकर बनाने में इन्वेस्ट इंडिया के योगदान का ब्यौरा क्या है;
- (ख) वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान इन्वेस्ट इंडिया द्वारा सुकर बनाए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है;
- (ग) वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल-सितम्बर, 2024) के पहले छह महीनों के दौरान इन्वेस्ट इंडिया द्वारा सुकर बनाए गए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार इन्वेस्ट इंडिया द्वारा प्रदान की गई निवेश सुविधा के कारण वास्तविक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में हुई वृद्धि का मूल्यांकन करने के लिए आंकड़े रखती है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) : राष्ट्रीय निवेश संवर्धन एवं सुविधाप्रदाता एजेंसी-इन्वेस्ट इंडिया का गठन वर्ष 2009 में, पूर्ववर्ती औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की 49% इक्विटी और फिक्की की 51% शेयरधारिता से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत किया गया था जिसका उद्देश्य विदेशी निवेश को बढ़ावा देना है। इन्वेस्ट इंडिया की वर्तमान शेयरधारिता का पैटर्न उद्योग संघों का 51% (अर्थात् फिक्की, सीआईआई और नैसकॉम प्रत्येक के लिए 17%) और भारत सरकार का 49% है। आज की तारीख के अनुसार, डीपीआईआईटी की 36% और 26 राज्य सरकारों (प्रत्येक राज्य का 0.5%) की 13% शेयरधारिता है।

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत, शेयरों से धारा 8 के अंतर्गत कंपनी लिमिटेड के रूप में गठित इस संगठन का व्यापक दृष्टिकोण भारत के आर्थिक विकास में सहयोग देना है। इन्वेस्ट इंडिया की स्थापना का उद्देश्य, भारत में रुचि दर्शाने वाले सभी निवेशकों के लिए प्रथम संदर्भ बिंदु के रूप में कार्य करना तथा एक ही स्थान पर सभी राज्यों के बारे में कर की दरों, कौशल उपलब्धता और राज्यों द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों जैसे मुद्दों पर जानकारी उपलब्ध कराना है। यह संगठन प्रचार-प्रसार का कार्य भी करता है तथा विशेष रूप से मेट्रो शहरों के दायरे से बाहर वैश्विक निवेशक जागरूकता के विस्तार के माध्यम से भी निवेश आकर्षित करता है।

सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने के उद्देश्य से निवेशक अनुकूल एफडीआई नीति लागू की है, जिसके तहत रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कुछ क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश क्षेत्र स्वतः अनुमोदन मार्ग के तहत 100% एफडीआई के लिए खुले हैं। स्वतः अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत लगभग 90% एफडीआई अंतर्वाह प्राप्त होता है। भारत ने एफडीआई की सीमा को बढ़ाते हुए, विनियामक बाधाओं को हटाकर, अवसंरचना का विकास और व्यावसायिक वातावरण में सुधार करके, वैश्विक निवेशकों हेतु अर्थव्यवस्था के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

(ख) और (ग) : इन्वेस्ट इंडिया ने वित्त वर्ष 2023-24 में कुल 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सांकेतिक निवेश वाली परियोजनाओं को सुविधा प्रदान की, जिसमें से 2.025 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से प्राप्त हुए हैं। इस निवेश में भारत के 10 राज्यों में स्थित 18 विदेशी कंपनियां शामिल हैं, जो वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, चिकित्सा उपकरण और ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हैं।

वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही (अप्रैल-सितंबर 2024) के दौरान कुल एफडीआई 42.10 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज किया गया है, जिसमें 29.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई इक्विटी अंतर्वाह शामिल है। इसी अवधि के दौरान, इन्वेस्ट इंडिया ने सात प्रमुख क्षेत्रों, अर्थात् ऑटोमोटिव, आईटी-बीपीएम, रसायन और उर्वरक, चिकित्सा उपकरण, शिक्षा, खेल और इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण (ईएसडीएम) से जुड़ी नौ विदेशी प्रत्यक्ष निवेश परियोजनाओं को सुविधा प्रदान की, जिसमें अनुमानित एफडीआई अंतर्वाह 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का है (कंपनी घोषणाओं के आधार पर)। ये निवेश छह देशों जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण कोरिया, युनाइटेड किंगडम, स्पेन और न्यूजीलैंड से आए हैं। लगभग 55.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर के औसत परियोजना आकार के ये निवेश, भारत की आर्थिक क्षमता में निरंतर अंतर्राष्ट्रीय विश्वास को दर्शाते हैं।

(घ) और (ङ) : एफडीआई अंतर्वाह केवल तभी दर्ज किया जाता है जब वास्तविक निधि हस्तांतरित की जाती है। निवेश के संबंध में प्रदान किए गए आंकड़े कंपनी की घोषणाओं पर आधारित हैं और कई वर्षों की परियोजना अवधि के दौरान प्राप्ति के अध्यधीन हैं। भारतीय रिजर्व बैंक और विदेशी निवेश सुविधा पोर्टल वास्तविक निवेश को ट्रैक करते हैं।
